P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
Vol-II * Issue-XI*July-2015

1857 की क्रान्ति के पश्चात् मेवातियों का स्वाधीनता संघर्ष में योगदान

मुबीना
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

सारांश

मेवात का इतिहास स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन की उपलब्धियों से भरपूर रहा है। विदेशी और भारतीय इतिहासकारों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में मेवातियों के योगदान पर अधिक नहीं लिखा है। मेवात पहाड़ी क्षेत्र था, इससे मेवों को हमेशा यह लाभ रहा कि वे दुश्मन पर अचानक हमला करके और उसे नुकसान पहुँचाकर पहाड़ों पर आसानी से जा कर छुप जाते थे।

मुख्य शब्द : स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मेवातियों।

प्रस्तावना

मेवात क्षेत्र में मेवों ने समय–समय पर दिल्ली साम्राज्य के विरूद्ध सफल ओर असफल विद्रोह किये व स्वयं को एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में पृथक से स्थापित करने का प्रयास किया।

1857 की क्रान्ति में मेवातियां द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किये गये जबरदस्त विद्रोह के कारण मेवात को कई भागों में बांट दिया गया, मेवात के कुछ भाग अलवर तथा भरतपुर रियासतों में मिला दिये गये तथा शेष भाग गुडगाव, मथुरा, आगरा तथा मेरठ जिलों में मिला दिये गये ताकि आगे आने वाले समय में मेव इकठ्ठे होकर अपनी ताकत न बढ़ा सके। परन्तु अपनी स्वाधीनता और अधिकारों के लिए मेवों का संघर्ष 1857 की क्रान्ति के बाद अंग्रेजी सरकार के साथ–साथ दो देशी रियासतों भरतपुर और अलवर के खिलाफ भी चलता रहा। इसके दो कारण थे– प्रथम यह कि अलवर प्रारम्भ से ही मेवों का राजनीतिक केन्द्र रहा था और दूसरा यह कि अब वह एक हिन्दू राजा के अधीन हो गया था जो मेवों को मुसलमान होने के कारण समय–समय पर परेशान करता रहता था। अंग्रेजों ने राजा अलवर और राजा भरतपुर की सहायता से मेवों को कुचलने की भरपूर कोशिश की। अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान मेव अंग्रेज अधिकारियों के साथ अक्सर मारपीट कर दिया करते थे। अंग्रेज तथा रियासतों के अत्याचार से परेशान होकर बाघोडिया पाल के दो मेव सरदारों घुडचड़ी व मेव खाँ ने अलवर रियासत के राजा मंगल सिंह (1874–1892) व अंग्रेजों को इतना परेशान किया कि उन्हें गिरफ्तार कर काले पानी की सजा दी गई थी।[1] आज भी मेव अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष में इनकी प्रेरणा लेते हैं।

सन् 1899 से 1900 तक मेवात में अकाल के वर्ष रहे। जिसके कारण हजारों की संख्या में मेवों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। सन् 1903 में मेवात में प्लेग की बीमारी फैल गई। यही बीमारी सन् 1924 में फिर फैली, जिसने लोगों की स्थिति को अत्यन्त दयनीय बना दिया। आर्थिक व जन शक्ति की इतनी हानि हुई कि मेवों की कमर टूट गई। सन् 1911 में दिल्ली में शाही दरबार लगा तो बड़ी संख्या में मेव उसे देखने के लिए दिल्ली गये और हालत से अवगत होकर आये। इस दरबार के कारण काफी लोगों को मजदूरी व दस्तकारी का काम मिला। अब कलकत्ता के बजाय अंग्रेजो ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था, संसद और गवर्नर हाऊस निर्माण के लिए जिन 14 गाँवों को विस्थापित किया गया उनमें मेव गाँव भी शामिल थे।

1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेज भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे, अतः मेवों से प्रतिबन्ध हटा लिया गया तथा भारी संख्या में मेव अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए और लड़ाई का सामना किया। अक्टूबर, 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वार चलाये गये खिलाफत आन्दोलन में भी मेवों ने भारी संख्या में भाग लिया।

1919 में रोलट एक्ट के विरोध में मेवात के नूँह, सोहना, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका में मेवों ने हड़ताल रखी तथा उसका डटकर विरोध किया। 1921–22 में मेवों ने गाँधीजी के आह्वान पर असहयोग आन्दोलन में बढ़–चढ़ कर भाग लिया। 29 दिसम्बर, 1021 को अपने 14 गिरफ्तार साथियों को रिहा

करवाने के लिए लगभग 200 मेवों आन्दोलनकारियों ने 'वन्दे मातरम्', 'अल्लाह–हो–अकबर' व 'गाँधीजी की जय' के नारों के साथ फिरोजपुर झिरका थाना व तहसील को घेर लिया। पुलिस थाने में जबरदस्ती से घुसने के कारण डिप्टी सुपरिन्टेण्डेन्ट ने हवाई फायर का आदेश दे दिया। तीन आदमी मौके पर ही मारे गये, अनेक आन्दोलनकारी घायल हुए। 31 मेव आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे गुस्सा आर बढ़ गया। आस–पास के गाँवों के मेवों ने हथियारों से लेस होकर थाने पर हमला बोल दिया। 21 घुड़सवारों का एक फौजी दस्ता राजा अलवर ने फिरोजपुर झिरका भेजा तथा गुडगाँव से भी एक दस्ता आ पहुँचा तब जाकर थाने व तहसील को बचाया जा सका। 13 आन्दोलनकारियों को दो–दो साल की कड़ी सजा दी गई तथा बाकी को रिहा कर दिया गया।

1922 में विधिवत् रूप से मेवात में कांग्रेस कमेटियाँ बनाई गई। डॉ. कुवर मोहम्मद अशरफ, सययद मुतल्लवी फरीदाबादी तथा चौ. अब्दुल हई (घुड़ावली) चौ. कंवल खाँ (आलीमेव), चो. रहीम खाँ (बीसरू), चौ. रहीम बक्श (सिंगार) मेवात में काँग्रेस के कर्मठ कार्यकर्त्ता थे। इन लोगों ने गाँव–गाँव जाकर काँग्रेस कमेटियों की स्थापना की, और मेव समुदाय के लोगों को काँग्रेस के उद्देश्यों से अवगत कराया,[2] तथा मेवों को आजादी की लड़ाई से विधिवत् रूप से जोड़ दिया। इसी वर्ष (1922) चौ. मुहम्मद यासीन खाँ के अथ्क प्रयत्नों से तत्कालीन डिप्टो कमिश्नर मि. एफ.एल.ब्रेन ने नूँह में ब्रेन मेव हाई स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल की स्थापना के साथ ही अनपढ़ तथा पिछडो हुई मेव जाति को आधुनिक शिक्षा के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई तथा वर्षो से शोषित और पिछड़ी हुई मेव कौम ने बड़ी दिलचस्पी के साथ सामाजिक और राजनीतिक जागृति की ओर कदम बढ़ाया। 1923 में चौधरी हयात खाँ पंजाब ऐसेम्बली के सदस्य चुने गये, सरकार में पहली बार मेवों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। चौ. मुहम्मद यासीन खाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गुड़गाँव के चेयरमैन चुने गये तथा बाद में 1926 से 1945 तक पंजाब ऐसेम्बली के सदस्य रहे।[3] इसी समय मेवात में सड़कों तथा प्राथमिक शिक्षा का काम शुरू हुआ।

फरवरी 1928 में जब साइमन ने बम्बई की भूमि पर पैर रखा तो मेवात में पूर्ण हड़ताल रही, सब जगह प्रदर्शन हुए। साइमन वापस जाओ के गगन भेदी नारों से सारा मेवात गूँज उठा। दिसम्बर 1929 में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ जिसमें भारत को पूर्ण आजादी देने की मांग की गई। मेवात से चौ. अब्दुल हई ने इस अधिवेशन में भाग लिया, जहाँ वे आजादी के जजबे से भरपूर होकर मेवात वापिस लौटे। मेवात के ग्राम सिंगार, बीसरू, आलीमेव, कोट, घुडावली, बहीन, पिनगंवा, पुन्हाना, हथीन, मालब, शिकरावा, बिछोर, घासेडा, रहना, फिरोजपर झिरका, नूँह, नगीना में काँग्रेस कमेटियों का गठन हुआ। मेवों ने बढ़–चढ़ कर आजादी की लड़ाई में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया।

परन्तु कुछ मेवों का सम्बन्ध मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी से भी था। क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी के नेता चौधरी मुहम्मद यासीन खाँ थे जो पंजाब ऐसेम्बली के सदस्य थे। मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन होने के नाते दूसरे मेव नेता इससे सम्बन्धित थे, जिनमें मोलाना कारी अहमद सौंद तथा महताब खाँ सिंगार प्रमुख थे जो पंजाब ऐसेम्बली के भी सदस्य रहे। चौ. यासीन खाँ के साथ अब्दुल रहीम बान्धोली भी पंजाब ऐसेम्बली के सदस्य रहे।

मेवात में इन पार्टियो के अतिरिक्त कम्यूनिस्ट पार्टी भी सक्रिय रही जिसके लिए डॉ. कुंवर मोहम्मद अशरफ और मौलवी इब्राहीम का प्रमुख योगदान रहा। इन्हीं के प्रयत्नों से फिरोजपुर झिरका और कोट में इसकी इकाइयाँ खोली गई।

1930 में सत्याग्रह के समर्थन में मेवात के रूपलाल मेहता, सैयय्द मुत्तलवी फरीदाबादी, चो. अब्दुल हई घुडावली प्रमुख आन्दोलनकारियों में से थे, जो कई बार जेल गये।[4]

अलवर तहरीक (आन्दोलन)

इस चेतना का परिणाम यह निकला कि सन् 1932 के आस–पास चौ. मुहम्मद यासीन खॉ और यूनियनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में भूमि कर न देने का आन्दोलन सरकार के खिलाफ छेड़ दिया, अलवर तहरीक रियासत के किसानों द्वारा 1932–33 में महाराजा सवाई जयसिंह के खिलाफ उस समय चलाई गई जब उसने मालगुजारी अचानक कई गुणा बढ़ा दी, गरीब किसानों पर अन्य टैक्स लगा दिये।

उस समय मेव प्रशासनिक तोर पर रियासत अलवर व भरतपुर तथा जिला गुड़गाँव तीन भागों में बंटे हुए थे। रियासत अलवर में मेवों की आबादी शेष सभी कृषक जातियों से अधिक थी तथा रियासत की आधी से अधिक कृषि योग्य भूमि पर उनका कब्जा था, इसलिए इस संघर्ष का सम्बन्ध मेवों से ही जुड़ गया।[5]

अलवर राजा सवाई जयसिंह जाति से क्षत्रिय नरूका राजपूत था। अलवर महाराजा तथा दो मेव पाल सींगल व देंहगल एक ही वंश कछवाहा से सम्बन्धित थे। मेवों ने अलवर रियासत की स्थापना में राजपूतों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर संघर्ष किया था।[6] इसलिए रियासत की स्थापना के पश्चात् शुरू में अलवर के राजाओं से मेवों के सम्बन्ध काफी मधुर थे[7] तथा मेवात के कुछ क्षेत्र माल गुजारी से मुक्त थे, मगर बाद में इस नीति को समाप्त कर दिया गया।[8] सन् 1932 में महाराजा जयसिंह ने अचानक मालगुजारी चार गुना बढ़ा दी। पशुओं पर छपाई टैक्स लगा दिया, हाथी टैक्स और नौकर टैक्स बढ़ा दिये, जिससे रियासत के किसान जो पहले से ही शोषण के शिकार थे ओर अधिक भड़क उठे।

इसके अतिरिक्त महाराजा की शिकार नीति अत्यन्त चिन्ताजनक एवं आक्रामक थी। महाराजा शूअर के शिकार का शौकीन था। जंगल में असंख्य सूअर पाल रखे थे जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे। सूअरों को मारना शख्त मना था, इसके अलावा खेतों की मेडबन्दी करने पर पाबन्दी थी, क्योंकि ऊँची मेड़ों के कारण गर्भवती सूरी आजादी के साथ नहीं घूम सकती थी। लोगों ने महाराजा के सामने अपनी परेशानियों को पेश किया, मगर उनके रूख में कोई परिवर्तन नहीं आया।

महाराजा अलवर भारतीय शहजादों की अंजुमन का अध्यक्ष था, जब कोई अंग्रेज अधिकारी या गर्वनर

जनरल भारत आता तो वह अलवर रियासत का मेहमान जरूर होता था, अतः वह अंग्रेजों का जबरदस्त हिमायती था, एवं उसे इंग्लैण्ड के राजा का पुत्र कहा जाता था।[9]

इन हालात ने रियासत की जनता को मजबूर कर दिया कि वह आर्थिक शोषण के विरोध में उठ खड़ी हो। महाराजा अलवर ने रियासत के प्रभावशाली लोगों को जिनमें मेव चौधरी भी थे, अपने दरबार में बुलाया और तीन दिन तक खूब सेवा की व बड़ी चतराई के साथ यह समझाने की कोशिश की गई कि रियासत का काम बिना टैक्स बढ़ाये नहीं चल सकता। चौधरी साहिबान जो महाराजा की सेवा से काफी खुश थे, मालगुजारी अदा करवाने का वादा कर अपने–अपने क्षेत्रों को लौटे, परन्तु तब तक रियासत की जनता पूरी तरह भड़क उठी थी। मेवों ने मालगुजारी देने से इन्कार कर दिया, जब कर्मचारियों ने जबरदस्ती मालगुजारी उगान की कोशिश की तो लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। कस्बों व गाँवों म मालगुजारी के विरोध में प्रदशन हुए, मालगुजारी उगाने की चौकियाँ बन्द कर दी गई। यह मेव पंचायत जिसका मुख्यालय नूँह था, पूरे भारत के मेवों का प्रतिनिधित्व करती थी। चौधरी यासीन खाँन इस पंचायत के अध्यक्ष थे तथा (1971 तक) आजीवन रहे, एवं चौधरी अब्दुल हई (घुडावली) इसके सचिव थे।

अलवर तहरीक (आन्दोलन) को शक्ति प्रदान करने के लिए ऑल इण्डिया मेव पंचायत के नीचे फिरोजपुर झिरका में अलवर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीम बक्श ने की, सम्मेलन में अम्बाला के सययद गुलाम भीख व मौलाना दाऊद गजनी भी थे। अलवर सरकार से मालगुजारी कम करने की मांग की गई।

फिरोजपुर झिरका में सम्मेलन के बाद अलवर आन्दोलन ने जोड़ पकड़ा, सारे भारत के अखबारों में इस आन्दोलन के समाचार प्रमुखता से छपने लगे। महाराजा अलवर काफी परेशान था परन्तु वह किसानों की उचित मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे डर था कि मांगे मान लेने पर वह कठपुतली राजा बन कर रह जायेगा, उसने गुप्त रूप से चौधरी मुहम्मद यासीन खाँ को एक भारी रकम तथा खिताब देने का वादा कर खरीदने की कोशिश की, कि वे अपना आन्दोलन वापिस ले ले, परन्तु वे इस कोशिश में असफल रहा।[10] इसके पश्चात् शिकार के बहाने चौधरी साहब पर गोलियाँ चलवाई, मगर वह बच गये, अब महाराजा अलवर की परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी।

चौ. मुहम्मद यासीन खाँ आन्दोलन के अपने विश्ववसनीय साथी सययद मुतल्लवी फरीदाबादी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विष्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. जियाउद्दीन के पास आन्दोलन के बारे में परामर्श करने व सम्मानजनक फैसला करने के बारे में विचार विमर्श करने गये। इसी दौरान सययद मुहम्मद टोंकी के माध्यम से मेव नेताओं की मुलाकत डॉ. कुंवर मोहम्मद अशरफ से हुई। चौधरी मुहम्मद यासीन खाँ ने लोगों से उनका परिचय कराते समय कहा कि डॉ. कुंवर मोहम्मद अशरफ अलवर रियासत की तहसील कठूमर के गाँव तसई से आये हैं, तसई गाँव पाहट पाल का है, जो मेवात व मीणावाटी की सीमा पर है, यह भी हमारा मेवाती भाई है।[11]

डॉ. अशरफ ने अलवर मुख्यालय की यात्रा की, वे फिरोजपुर झिरका के बड़े–बड़े मेव गाँवों में गये। वे उन हथियार बन्द लोगों से भी मिले जो महाराजा की फौजों से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते थे। उनकी बन्दूकों, बारूद तथा रायफलो का निरीक्षण किया, लोग सुनकर हैरान रह गये जब डॉ. साहब ने उन्हें बताया कि अच्छा बारूद किस प्रकार बनाया जाता है। उन्होंने ऑल इण्डिया मेव पंचायत के कार्यालय व इसके कार्यो का भी निरीक्षण किया। कार्यकर्त्ताओं को आवश्यक सलाह दी और बताया कि कार्यालय की पत्रावलियों व आवश्यक रिकार्ड को किस प्रकार रखा जाय।

इन दिनों चौ. अब्दुल हई जो पहाड़ ऊपर क्षेत्र के इन्चार्ज थे तथा मुंशी यूसुफ खाँ फिरोजपुर नमक पहाड़ के नीचे क्षेत्र को देख रहे थे, से डॉ. साहब मिले तथा उनका हौंसला बढ़ाया। अलवर रियासत की कमजोरियॉ बताई, जिससे लोगों में नया जोश आ गया, आन्दोलन के लिए चन्दा लेने का काम प्रारंभ किया। आन्दोलन की आमदनी बढ़ने लगी तथा नये जोश का संचार होने लगा।[12]

डॉ. अशरफ के अलवर आन्दोलन में शामिल हो जाने पर महाराजा अलवर काफी चिन्तित हुए। वे महाराजा के निजी सचिव रह चुके थे तथा रियासत की कमजोरियों से भली–भाति परिचित थे, रियासत के हितों को काफी नुकसान पहुँचा सकते थे।

अब पूरी रियासत में अशांति, बदइन्तजामी व असंतोष की लहर फैल गई थी। इन कठिन परिस्थितियों में भी महाराजा के सलाहकार उन्हें बीच का रास्ता अपनाने के बजाय सख्ती व जुल्म के रास्ते पर चलने की ओर उकसा रहे थे।

डॉ. अशरफ व चौधरी यासीन ने लोगों की मांगों को सही रूप में लिखकर अंग्रेजी सरकार को भेज दिया। इसकी रिपोर्ट अखबारों में भी छपी, जिसे केन्द्रीय सरकार विदेशी प्रतिनिधि व दश के दूसरे नेताओं में भी बांटा गया। जनता की परेशानियों व रियासत के अन्याय के समाचार अखबारों में छपने लगे। 1933–34 में महाराजा से पद त्यागने की मांग की गई, तो सारा देश स्तब्ध रह गया।

महाराजा बराबर शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, मगर वह जितना शक्ति का प्रयोग करता, उसकी उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया जनता में होती। तिजारा और किशनगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र के लोग सैनिक दृष्टि से अच्छो स्थिति में थे, परन्तु गोविन्दगढ़ की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। महाराजा को समाचार मिला कि गोविन्दगढ़ में मेवों की एक पंचायत हो रही है जो आन्दोलन के लिए चन्दा उगाने के तरीकों पर विचार–विमर्श करेगी। रियासती फौज ने लोगों को चारों ओर से घेर लिया। निहत्थे लोगों पर मशोनगनों से अन्धाधुन्ध फायरिंग प्रारम्भ कर दी, सैकड़ों निर्दोष मेवाती फायरिंग में मारे गये तथा असंख्य लोग घायल हुए।[13] इस घटना की सारे देश में सनसनी फैल गई। इस घटना ने पहले से ही नाराज केन्द्रीय सरकार को मजबूर कर दिया कि वह रियासत के

अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करें। अतः ब्रिटिश सरकारी फौजी दस्ते तुरन्त अलवर पहुँच गये तथा महाराजा के सारे अधिकार छीन लिए। महाराजा को दो वर्ष के लिए देश से बाहर भेज दिया, उसी दौरान पेरिस के एक होटल में उनका निधन हो गया।

रियासत की नई सरकार ने गुड़गाँव व अलवर के मेव फौजी सरदारों की मदद से रियासत में शांति बहाल की, लगान का एक चौथाई भाग कम कर दिया गया। दूसरे नाजायज टैक्स हटा दिये। बड़े–बड़े गाँवों में स्कूल खोले गये, रियासत छोड़कर भाग गये लोगों को फिर बसाया गया, मेवों को रियासत की नौकरियों में भर्ती किया गया, केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप पर चौधरी मुहम्मद यासीन खाँ व उनके साथियों ने इस आन्दोलन को वापिस ले लिया। इस प्रकार एक लम्बे संघर्ष का सफल अन्त हुआ।

रियासत में शान्ति स्थापित करने में खान बहादुर सरदार मुहम्मद खाँ (बींवा) व खान साहिब सूबेदार महमूद–उल–हसन (खैंचातान) की सेवाएँ सराहनीय रहीं। इस आन्दोलन के बाद सयय्द मुत्तल्लवी व उनके नौजवान साथी डॉ. कुंवर मोहम्मद अशरफ कॉंग्रेस में शामिल हो गये। अब उनका उद्देश्य मेवों की संगठन शक्ति व संघर्ष क्षमता का उपयोग देश की स्वतंत्रता आन्दोलन में करने का था।

अलवर (तहरीक) आन्दोलन की सफलता एवं महाराजा अलवर की बर्खास्तगी तथा अलवर के किसानों को मिली आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक रियायतों का प्रभाव, रियासत भरतपुर के किसानों पर भी पड़ा। इन्होंने भी इरादा किया कि अलवर जैसा आन्दोलन रियासत भरतपुर में भी चलाया जाय, ताकि उन्हें अलवर जैसी सुविधाएँ मिल सके। रियासत के जागीरदारों के अत्याचारों, बन्धुवा मजदूरी तथा किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार ने भी मेवों को आन्दोलन के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मालगुजारी अदा न करने का विचार पूरे मेवात क्षेत्र में फैल चुका था।[14]

राजा भरतपुर किशन सिंह मेवों की आन्दोलनकारी जागृति से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने मेवों के साथ संघर्ष को अत्यन्त हानिकारक समझा। महाराजा ने चौ. अजमत खाँ तथा दूसरे मेव नेताओं से सम्बन्ध स्थापित किये रियासत का दीवान मि. बत्रा जो कुशल् राजनीतिज्ञ था, ऑल इण्डिया मेव पंचायत के नेताओं से मिलने नूँह गया, उसने चौ. यासीन खाँ, अब्दुल हई, सयय्द मुतल्लवी से विचार–विमर्श किया तथा मेवों को अधिक आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक सुविधाएँ देने का वायदा किया तथा विश्वास दिलाया कि रियासत द्वारा मेवात क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

1938 भरतपुर रियासत में ज्यादतियों के विरूद्ध किशन लाल जोशी ने प्रजा परिषद् का गठन किया, उसके अन्य सहयेागी थे, गोपीलाल यादव, मा. आदित्येन्द्र, युगलकिशोर चतुर्वेदी, बाबू राजबहादुर[15] तो मेव भी रियासत के हिन्दुओं के साथ इसमें शामिल हो गये, जिनमें डॉ. कुंवर मोहम्मद अशरफ, चौ. अब्दुल हई, चौ. कंवल खाँ, चौ. अमीर खाँ खेस्ती, चौ. सफात खाँ, मादलका आदि प्रमुख थे। इन लोगों ने भरतपुर के साथ–साथ गुड़गाँव के मेवों को भी प्रजा परिषद के आन्दालन में भाग लेने के लिए आह्वान किया। महाराजा भरतपुर ने रियासत मे प्रजा परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया, इसलिए पुन्हाना में एक विशाल सभा बुलाई गई, जिसमें भारी संख्या में मेवों ने भाग लिया। डॉ. कुंवर मोहम्मद अशरफ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, उन्होंने प्रजा परिषद् के इस आन्दोलन तथा सत्याग्रह में बढ़–चढ़ कर भाग लेने के लिए मेवों का आह्वान किया।

नौगाँवा पर महाराजा की फौज ने आक्रमण करके परास्त कर दिया तो आन्दोलन समाप्त हो गया, क्योंकि यह गाँव भरतपुर रियासत की सीमा पर स्थित अन्तिम मेव गाँव था, यहाँ उत्तरप्रदेश व गुड़गाँव मेवात की सीमाएँ मिलती है, महाराजा ने इस गाँव पर फौजी हमला यह सोचकर किया कि गुड़गाँव के मेव, रियासत के मेवों से सम्बन्ध स्थापित न कर सके तथा उत्तरप्रदेश के जाट रियासत की मदद करने पहुँच जाय, ताकि आन्दोलन को आसानी स कुचला जा सके।

भरतपुर आन्दोलन पढ़े लिखे लोगों का आन्दोलन था, जिसमें रियासत के लोगों की भलाई व विकास के लिए मांग की गई, जबकि अलवर तहरीक एक किसान आन्दोलन था जो महाराजा अलवर की गलत नीतियों, अनुचित टैक्सों द्वारा किसानों का शोषण तथा रियासत के अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के विरूद्ध था। अतः भरतपुर आन्दोलन एक राजनीतिक आन्दोलन था जो लोगों की भलाई तथा शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी के लिए शुरू किया गया था।

अलवर आन्दोलन के पश्चात् सयय्द मुतल्लवी फरीदाबादी, चौ. अब्दुल हई, चौ. कमल खाँ व उनके अन्य साथियों ने मेवात में कॉंग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन किया। 1940 के सत्याग्रह आन्दोलन में मेवों ने गाँधी जी को भरपूर सहयोग दिया। ग्राम आली मेव में सत्याग्रह आन्दोलन के समर्थन में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में चौ. अब्दुल हई ने लोगों से अंग्रेज सरकार को उखाड़ फैकने का आह्वान किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ देने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से सरकार को कर अदा न करने व अंग्रेजी फौजों में भर्ती न होने की अपील की। फलस्वरूप उन्हें 5 मार्च, 1941 को गिरफ्तार कर शाहपुर कैम्प जेल में डाल दिया गया, बाद में काफी दिनों तक रावलपिण्डी जेल में भी बन्द रहे।[16]

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में मेवों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। मेवात में जगह–जगह सभाएँ हुई, जिनमें कॉंग्रेस के कई नेताओं जिनमें डा. सज्जाद जहीर, डॉ. के.एम. अशरफ, सहजादा महमूद–उल–जफर, बेगम डॉ. रशीद, पं. श्रीराम शर्मा, पं. नेकराम शर्मा तथा रूपलाल मेहता थे, ने भाग लिया। आखिर देश भक्तों के अथक प्रयासों एवं कुर्बानियों के पश्चात देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ।

पाल प्रदेश की स्थापन की काशिश

मेव व हिन्दू जाट पीढ़ियों से अच्छे पड़ौसियों की तरह मेल–मिलाप के साथ रहते आये थे। 1942 में कुछ हिन्दू फिरका परस्तों ने जाटों को तथा कुछ मुस्लिम

फिरकापरस्तों ने मेवों को भडकाना शुरू कर दिया।[17] फलस्वरूपों चोरी की एक घटना से कोट के मेव छिरकलौत पाल तथा बहीन के जाट रावत पाल में घमासान लड़ाई हो गई। जाटों के साथ उनके गाँवों में रहने वाले मेव तथा मेवों के साथ उन गाँवों मे रहने वाले हिन्दू तथा उनकी पाल से लगने वाले जाट साथ थे। लड़ाई के बाद दोनों पक्ष अपने–अपने मृतकों को ले गये और एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर किया। पुलिस ने सैकड़ों जिम्मेवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही दोनों पक्ष थाने में मिले, उन्होंने फैसला करने के लिए एक पंचायत बुलाने का निश्चय किया। जिसमें डॉ. मोहम्मद अशरफ और सयय्द मुतल्लवी विशेष तार से आमंत्रित किये गये। इसी घटना से प्रेरणा लेकर सयय्द मुतल्लवी ने चौ. अब्दुल हई के नाम से एक अपील छपा कर बॅटवाई, जिसमें मेवात व इसके आस–पास के क्षेत्रों को मिलाकर पाल प्रदेश की स्थापना पर विचार करने की अपील की गई।[18]

करांची प्रस्ताव की रोशनी मे लोग आजाद भारत में नये प्रदेशों की रचना करने को योजना बना रहे थे तो डॉ. अशरफ व सयय्द मुतल्लवी ने मेवात व उसके साथ लगते हुए क्षेत्रों को मिलाकर पालप्रदेश की स्थापना का सुझाव दिया, जिसमें अलवर, भरतपुर व गुड़गाँव के मेवात क्षेत्र के अलावा इसमें सम्पूर्ण अलवर, भरतपुर रियासत सम्पूर्ण जिला गुडगाँव, आगरा तथा मेरठ डिवीजन तथा देहली शहर को छोड़कर दिल्ली राज्य को शामिल करने का सुझाव रखा गया, क्योंकि यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परम्पराएँ एक जैसी है।

डॉ. अशरफ का विचार था कि पाल प्रदेश में हिन्दू मुस्लिम, अमीर, गरीब सबका बराबर स्थान रहेगा। सत्ता लोकप्रिय नेताओं के हाथ में रहेगी, मेवात तथा इसके साथ लगते क्षेत्र के हिन्दू तथा मुस्लिम पाल प्रदश की स्थापना पर सहमत थे। परन्तु कुछ लोगों ने इसे हास्यापद प्रस्ताव बताया और इसकी तीखी आलोचना की, पाल प्रदेश को मिनी पाकिस्तान तथा डॉ. अशरफ को दूसरा जिन्ना की संज्ञा दी।[19]

यह वह समय था जब भारत विभाजन पर चर्चाएँ होती थी तथा मुस्लिम नेताओं की तरफ से आने वाले अच्छे प्रस्तावों को भी सन्देह की नजर से देखा जाता था। इसके बावजूद पाल प्रदेश के समर्थकों ने स्थान–स्थान पर मीटिगें की तथा समर्थन प्राप्त किया। अशरफ तथा मुतल्लवी ने ग्राम नौगाँवा तहसील फिरोजपुर झिरका में एक विशाल पंचायत बुलाई जिसमें सैकडों मेव व जाट चौधरियों ने भाग लिया, मगर अंग्रेज सरकार पाल प्रदेश के विचार से इतनी डर गई कि उसने गाँव में धारा 144 लगा दी। परन्तु कुछ समय पश्चात् यूनियनिस्ट जाटों ने भी पाल प्रदेश का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, वे उत्तरी भारत के जाट बाहुल्य क्षेत्र को मिलाकर जाट प्रदेश की स्थापना करना चाहते थे। काँग्रेस के कुछ लोग भी इस विचार के विरोधी हो गये। अलवर तथा भरतपुर रियासत में लोकप्रिय सरकारों के गठन की मांग ने दोनों रियासतों के राजाओं को पाल प्रदेश के विरूद्ध कर दिया, यहाँ तक कि जमाअत–ए–उलेमाएँ हिन्द भी इसकी विरोधी हो गई। तत्पश्चात् भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्थापना, रियासतों का एकीकरण, हिन्दू–मुस्लिम दंगे सब एक साथ आ गये, जिससे पाल प्रदेश का विचार जलकर राख हो गया।[20]

1947 और उसके पश्चात्

अंग्रेजों को लगभग 150 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात् 1947 में भारत छोड़ना पड़ा और देशवासियों के एक लम्बे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई। अंग्रेजी सरकार ने जाने से पहले ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी, जिनकी वजह से देश में जगह–जगह साम्प्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गये। गाँधीजी ने उन सभी साम्प्रदायिक लोगों का, जो इस प्रकार के दंगों के पक्ष में थे, हिम्मत से मुकाबला किया। साम्प्रदायिक भावना फैलाने वाले लोगों ने ही गाँधीजी को गोली मारकर शहीद कर दिया।

मेवात क्षेत्र पर साम्प्रदायिक दंगों का बहुत ज्यादा असर पड़ा। अलवर तथा भरतपुर राजाओं ने साम्प्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर कत्ल–ए–आम प्रारंभ कर दिया। अकेले भरतपुर में 30,000 मव रियासत फौज की गोलियो के शिकार हुए, रियासत अलवर में लगभग 40,000 मेवों को शुद्धि किया गया।[21]

अलवर रियासत के प्रधानमंत्री ठाकुर रघुवीर सिंह ने मेवों को शुद्धि करने का प्रबन्ध किया, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों को एक तालाब पर ले जाया जाता, दाढियाँ करवा दी जाती, चोटी के अलावा सिर के बाल साफ कर दिये जाते। उसके बाद उन्हें तालाब में स्नान कराया जाता, फिर हवन में भाग लेने के लिए कहा जाता। स्त्रियों को साडियाँ पहनाई जाती। छः महीने तक अलवर रियासत का प्रत्येक मेव हिन्दू था, इसके पश्चात् विनोबा भावे ने मेवात का दौरा किया तथा मेवों को इस्लामिक तरीके से जीने के लिए उत्साहित किया।[22]

20–21 जून, 1947 को कामाँ और भरतपुर के सारे मेव गाँव दंगाइयों ने जलाकर राख कर दिये, भरतपुर राज्य की फौजे मेवों पर आक्रमण व लूटमार कर गाँवों को आग लगा रही थी, मेवों ने परेशान होकर अपने घरों को खुद भो आग लगा ली थी, ताकि लूटरों के हाथ कुछ न लगे।[23]

जुलाई, 1947 के अन्तिम सप्ताह में ही भरतपुर रियासत के सारे मुसलमान रियासत अलवर तथा गुड़गाँव की ओर निकाल दिये गये। 15 अगस्त को अलवर राज्य की फौज तिजारा पहुँची तथा रियासत के नाजिम चौ. बरकत–उल्लाह सहित काफी संख्या में मुसलमान फौजी अत्याचार के शिकार हुए। 4 सितम्बर से 7 सितम्बर तक डीग व कुम्हेर के मुसलमानों का साम्प्रदायिकों ने कत्ले–आम किया, 9 व 10 सितम्बर को बयाना व भरतपुर पर धावा बोल दिया। इसके बाद ही मेवात के उत्तर–पूर्वी जाट जाति के गाँवों के लोगों ने एक विशाल धाड (अनुशासित लोगों का समूह) बनाकर नीमका, नई, बिछोर, दाड़का, इन्दाना आदि गाँवों पर हमला कर आग लगा दी। बीवां, धौलेट, नोगाँवा के सैकड़ों मेवों का इस दौरान कत्ले–आम हुआ। रियासत अलवर में मण्डावर के पास 12 मेव गाँवों को जलाकर राख कर दिया। इस दौरान शांति स्थापित करने के लिए कई बार हिन्दु–मुस्लिम पंचायतें हुई, परन्तु साम्प्रदायिक ताकतों ने इन्हें कामयाब नहीं होने

दिया, लाखों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़ दिया तथा मजबूर होकर शिविरों में आ गये।

इस दोरान अन्दरूनी मेवात (गुड़गाँव) में पूर्ण शान्ति थी व पूरा जिला, रियासत अलवर व भरतपुर से आने वाले बर्बाद मेवों की शरण स्थली बना हुआ था। लोग हर तरह से अपने पीड़ित मेव भाईयों की मदद कर रहे थे।

पाकिस्तान बन जाने के बाद मेवात क्षेत्र के मेवों की बड़ी संख्या इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद भी अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मगर साम्प्रदायिक लोग उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान धकेलना चाह रहे थे। डॉ. कुंवर मोहम्मद अशरफ ने गाँधीजी को मेवात के हालात से वाकिफ कराया। गाँधीजी उस समय देहली में थे, इसलिए वे मेवात के हालात से वाकिफ होकर हुमायूँ के मकबरा के पास लगे कैम्प में ठहरे हुए मेवों से मिलने गये।[24] जहाँ तबाह और बर्बाद मेवों ने गाँधी जी को आप बीती सुनाई। देहली डायरी में लिखा है कि ''आप मेव शरणार्थियो से मिलने कैम्प गये जो मकबरा हुमायूं के नजदीक था। मेवों ने गाँधीजी को बताया कि उनको अलवर और भरतपुर रियासतों से निकाल दिया गया है वे केवल उस खाने पर गुजारा कर रहे हैं जो उनके मुसलमान दोस्त भेज रहे हैं। गाँधोजी मानते थे कि मेव जल्दी ही देश में आकर मुसीबत का कारण बन सकते हैं मगर इसका यह इलाज नहीं था कि उनको उनकी इच्छा के खिलाफ पाकिस्तान भेज दिया जाय, बल्कि सही तरीका तो यह था कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रारम्भ करके उनकी कमजोरियों का इलाज बीमारियों के इलाज की तरह किया जाय।

दूसरी बार गाधी जी 19 दिसम्बर, 1947 को मेवों के गाँव घासेडा में गये, जो दिल्ली–अलवर सड़क पर स्थित है। दिल्ली से 42 मील दूर इस गाँव में उन्होंने लोगों को सम्बोधित किया। अपने भाषण में कहा 'मेव हिन्दुस्तान की रीढ़ हं, उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री डॉ. गोपनीचन्द भार्गव व चौ. मुहम्मद यासीन खाँ भी थे।' देहली डायरी में लिखा है कि आज शाम प्रार्थना के बाद गाँधीजी ने उपस्थित लोगों को बतलाया कि वे उन मेवों से मिलने गये जो बेघर हो गये थे, इनकी बड़ी संख्या अलवर व भरतपुर रियासतों से निकाल दी गई थी। कुछ लोग पाकिस्तान चले गये बाकी डांवाडोल थे। ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वे कहाँ रहे, पाकिस्तान में या भारत में। डॉ. गोपीचन्द ने मेव लोगों को विश्वास दिलाया कि जो अपने देश में रहना चाहते हैं, उनका हक है कि वो यहाँ रहे। सरकार उनकी जान–माल की रक्षा करेगी। गाँधी ने कहा कि वो देश छोड़ने के हक में नहीं है। लाखों औरतों, मर्दो और बच्चों को उनके घर से निकालना बुरा काम था। इन परिस्थितियों के हालात में ये सोचना कि जुल्म किस तरफ से हुआ, बेकार था। इस तरह की बातों से शांति स्थापित नहीं हो सकती, जो खुशी से जाना चाहते थे, उन्हें जाने की पूरी स्वतन्त्रता थी। कुछ लोगों का यह कहना था कि मेव लोग अपराधी होते हैं, अगर उन पर यह अरोप सही भी हैं तो सरकार उन्हें देश से बाहर नहीं निकाल सकती, बल्कि ठोस तरीका यह है कि उनका सुधार किया जाय और आधुनिक शिक्षा से अवगत कराया जाय।[25]

भरतपुर और अलवर के मेवों के लिए जिला गुड़गाँव का प्रत्येक गाँव शरण देने का शिविर बन गया। ये लोग सब कुछ छोड़कर आये थे, मगर फिर भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हालात खराब हो। जो लोग पाकिस्तान नहीं गये वे काफी समय तक गुड़गाँव जिले के गाँवों में रहें, जो लोग पाकिस्तान से वापिस आना चाहते थे उन्हें आने की खुली इजाजत थी। गाँधी जी को मेवों से गहरी हमदर्दी थी। जिनके कारण पंजाब और राजस्थान सरकार के रवैये में परिवर्तन आया, शिविरों में बसे हुए मेवों ने पाकिस्तान जाने का इरादा त्याग दिया।

इसके पश्चात् लोगों को उनके गाँवों में पुनः आबाद करने के प्रयत्न प्रारम्भ हुए। ठीक एक वर्ष बाद जून–जुलाई, 1948 में पुनर्वास का कार्य प्रारम्भ हुआ। भारत के पुनर्वास मन्त्री जन. भौसले, पं. जीवनलाल, सत्यम भाई, अब्दुल हइ, चौधरी मोहम्मद अशरफ खाँ, चौ. यासीन खाँ, मौलवी इब्राहीम आदि ने मेवों के पुनर्वास के मामले में अत्यन्त परिश्रम और ईमानदारी से काम किया। उजड़े हुए लोगों के मकानों की गाँव–गाँव जाकर सूचियाँ बनाई जो लोग गणना में छूट गये थे, उनकी पहचान कराके उनके परिवारों की समस्याओं का निराकरण किया गया।

मौलाना इब्राहीम ने जो बाद में काँग्रेस के टिकिट पर कामाँ से विधायक बने, जमाअत–ए–उलेमाएँ हिन्द के मंच से काम किया, लोगों को पुनः बसाने तथा उनका आत्म–विश्वास बहाल करने के लिए दिन–रात एक कर दिया। चौ. मुहम्मद यासीन ने लोगों का पुनर्वास कराने तथा उनके आत्म विश्वास पैदा करने के लिए जगह–जगह सभाएँ की जिन्हें काँग्रेस के कई बड़े–बड़े नेताओं ने सम्बोधित किया जिनमें लाला भीमसेन सच्चर, मो. अब्दुल गनी डार, केदारनाथ साहनी, बाबू बच्चन सिंह, सरदार सज्जन सिंह, मौलाना जैबर्रहमान, लुधियानवी, उनके निमन्त्रण पर मेवात आयें और लागों का आत्मविश्वास बढ़ाया।

सभी प्रत्यनों के बावजूद लाखों मेव पाकिस्तान चले गये। पाकिस्तान के लाहौर, स्यालकोट, सरगोदा, मुलतान, लायलपुर आदि जिलों में मेवों की भारी आबादियाँ हैं, मगर वे आज भी मेवात को नहीं भूल पाये हैं। इस प्रकार उजड़े हुए मेव एक बार फिर आबाद हो गये तथा शांति एवं सद्भाव से रहने लगे।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपनी स्वतन्त्रता, ऐतिहासिक संस्कृति तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए मेवों ने निरन्तर संघर्ष किये। अपनी मातृभूमि को निरन्तर अपने खून से सींचते रहें, उनकी बिरादरी व्यवस्था इतनी मजबूत तथा ईमानदार थी कि उनके गाँव एक छोटी सी रियासत नजर आते थे। सी.टी. मेटकॉफ के अनुसार 'ये ग्राम बिरादरियाँ छोटे–छोटे राज्यों की भाँति हैं, इन पर किसी का बाहरी दबाव व नियन्त्रण नहीं है, अपना सब काम स्वन्तत्र रह कर करते हैं, कितने ही राजवंशों का पतन हो गया, कितनी ही क्रांतियाँ आई और

समाप्त हो गई, हिन्दू, पठान, मुगल, मराठे, सिक्ख व अंग्रेज बारी–बारी से आये परन्तु ग्राम बिरादरियाँ वैसी की वैसी ही बनी रही है।[26]

मेवों के सुदृढ़, सामाजिक संगठन में हमेशा विदेशी हमलावरों ने सेंध लगाने की कोशिश की परन्तु वह यथावत बना रहा। मेवों की इन ग्राम बिरादरियों ने अतीत में कई ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण फैसले किये औरंगजेब के विरूद्ध संगठित होकर दारा का साथ देना, मराठा फौजों और अंग्रेजों का मिलकर विरोध करना, अलवर (तहरीक) आन्दोलन, कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक फैसले थे, जिनसे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मेवों की ग्राम बिरादरी व्यवस्था कितनी सृदृढ़, अनुशासित व मजबूत थी। अब सवाल उठता है कि मध्यकालीन इतिहासकारों ने मेवों को डाकू या लुटेरे क्यों कहा है। मगर प्रश्न उठता है कि क्या कोई पूरी कौम डाकू हो सकती है? यदि ऐसा भी है तो उनके लिए खाने का सामान कहाँ से आता। फिर मेव दिल्ली को ही क्यों लूटते, दिल्ली के अलावा उन्होंने अपने ईद–गिर्द दूसरे शहरों–बयाना, आगरा, मथुरा, अलवर, भरतपुर, रेवाड़ी आदि पर क्यों धावे नहीं बोले, जबकि सामरिक दृष्टि से दिल्ली इन सभी शहरों से अधिक सृदृढ़ था।

मध्यकालीन सुलतानों को मेवों के छापामार दस्तों ने इतना पेरशान किया था कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। सन् 1857 में अंग्रजों की जितनी परेशानी मेवों का काबू करने में हुई, उतनी परेशानी उन्हें शायद ही कही हुई हो। इन परिस्थतियों में इनके इनाम के लालची इतिहासकारों ने डाकू व लूटेरे के जैसे खिताब दिये, क्योंकि वे मेव ही थे जो विदेशी शासकों का दिल्ली के दामन में रहकर समय–समय पर विरोध करते रहे। इस मेवाती दोहे से इस तथ्य की पुष्टि होती है–

दिल्ली पे धावों करो, अपणापन की जाण।
डरपा मेवन सू सदा, खिलजी मुगल पठाण।।

संदर्भ सूची

1. अनिल जोशी 'मेवाती बात साहित्य' पृ. 35
2. मौलबी अब्दुल शकूर 'तारीख–ए–मेव क्षत्रीय' पृ. 323
3. चौ. अब्दुल हई 'चौ. मौ. यासीन खाँ जीवन परिचय', यासीन खाँ यादगार कमेटी, नूँह जिला गुड़गाँव, पृ.9
4. मुहम्मद अशरफ 'मेव कौम और मेवात' पृ. 147–148
5. पूर्वोक्त पृ. 152–153
6. अब्दुल हई 'दी फ्रीडम मूमैण्ट इन मेवात एण्ड डॉ. के. एम. अशरफ' (सम्पादित होर्स्ट क्रूजर) 'कुंवर मोहम्मद अशरफ : एन इण्डियन स्कोलर एण्ड रिवोल्यूशनरी 1903–1962' पियूपिल्स पब्लिशिंग हाउस देहली, 1969. पृ. 295
7. मौ. अब्दुल शकूर पूर्व उद्धृत, पृ. 477
8. अब्दुल हई 'दी फ्रीडम मूमेण्ट इन मेवात एण्ड डॉ. के. एम. अशरफ', पृ. 295
9. पूर्वोक्त पृं. 301
10. चौ. अब्दुल हई 'चौ. मौ. यासीन खाँ जीवन परिचय', पृ. 12
11. होर्स्ट क्रूजर 'कंवर मोहम्मद अशरफ : एन इण्डियन स्कोलर एण्ड रिवोल्यूशनरी 1903–1962', पृ. 301
12. मौ. अब्दुल शकूर पूर्व उद्धृत, पृ. 481
13. बी.एल. पानगडिया 'राजस्थान का इतिहास' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1996 पृ. 717,
14. होर्स्ट क्रूजर पूर्व उद्धृत, पृ. 302
15. बी.एल. पानगडिया पूर्व उद्धृत प. 124
16. हकीम अजमल खाँ लेख 'स्वतंत्रता संग्राम में मेवों का योगदान' मेव टाइम्स अंक–5, सितम्बर 1987, नई दिल्ली
17. मौ. अशरफ पूर्व उद्धत, पृ. 150
18. होर्स्ट क्रूजर पूर्व उद्धत, पृ. 306–307
19. पूर्वोक्त, पृ. 314
20. पूर्वोक्त, पृ. 314
21. पी.सी. अग्रवाल 'कास्ट रिलीजन एण्ड पॉवर इन इण्डियन केस स्टेडी', पृ.49
22. पूर्वोक्त, पृ. 50
23. मौ. अब्दुल शकूर पूर्व उद्धृत, पृ. 513
24. गाँधीजी 'देहली डायरी' नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदाबाद मार्च, 1948, पृ. 53
25. गाँधीजी, 'देहरी डायरी', पृ. 267
26. के.सी. यादव, 'हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति,' भाग–2, पृ. 44